RNI NO. : MAHHIN/1998/02261

महाराष्ट्र क्राईम्स

वर्ष 22 | अंक 11 | मुंबई, 05 सितंबर, 2023 | पृष्ठ : 8 | कीमत : 5 रुपये | प्रधान संपादक : सिराज चौधरी

जन्माष्टमी और गणेश
उत्सव की हार्दिक शुभेच्छा
महाराष्ट्र क्राईम्स
परिवार

महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाईन लॉटरी पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी लॉटरी माफिया सक्रिय

आर.सी.एफ. पुलिस थाना क्षेत्र में खुलेआम चल रही है अवैध ऑनलाईन लॉटरी

विवेक फणसलकर
पुलिस आयुक्त
मुंबई

विनायक देशमुख
अपर पुलिस आयुक्त
पुर्व प्रादेशिक विभाग

हेमराजसिंह राजपूत
पुलिस उपायुक्त परिमंडल
क्रमांक 6

मुरलीधर करपे
आर.सी.एफ.पुलिस थाने के
वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक

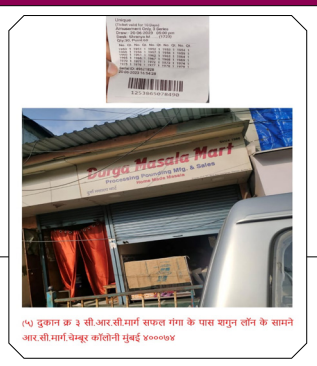

६) दुकान क्र २ एस.वि.पी.नागर मच्छी माकेट के सामने फ्री वे वाशी नाका ब्रिज के निचे चेम्बूर ४०००७४

अपर पुलिस आयुक्त पुर्व प्रादेशिक विभाग, पुलिस उपायुक्त परिमंडल क्रमांक 6 को अवैध ऑनलाईन लॉटरी की शिकायत करने पर आर.सी.एफ.पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मुरलीधर करपे ने गुंडो को घर भेजकर दी जान से मारने की धमकी

(२) बिल्डिंग क्र ६ के सामने, के जी एन चिनेसे कार्नर के बाजु में चेम्बूर कैंप चेम्बूर कॉलोनी चेम्बूर मुंबई ७४

(३) दुकान क्र ३ साबरी शिवम् के सामने नित्यानंद बाग रोड ड्रीम्स प्रोपर्टी के बगल में चेम्बूर कॉलोनी मुंबई ४०००७४

(५) दुकान क्र ३ सी.आर.सी.मार्ग सफल गंगा के पास शगुन लॉन के सामने आर.सी.मार्ग.चेम्बूर कॉलोनी मुंबई ४०००७४

(१) दुकान क्र ४ एम.एस.बिल्डिंग क्र १७ नित्यानंद बाग रोड आर.सी. मार्ग चेम्बूर कॉलोनी मुंबई ४०००७४ (२) बिल्डिंग क्र ६ के सामने चेम्बूर कैंप चेम्बूर कॉलोनी चेम्बूर मुंबई ७४

(३) दुकान क्र २ बी.जे.पी कार्यालय के पीछे वासवानी बुक स्टोर के पास डॉ सी.जी.रोड जय जलाराम बुक स्टोर के बगल में चेम्बूर कॉलोनी मुंबई ४०००७४

(७) आशीष सिनेम के पास लक्ष्मी कोलोनी मरोली चर्च के सामने माहुल रोड चेम्बूर मुंबई ४०००७४

महाराष्ट्र क्राइम्स
विशेष संवाददाता

मुंबई : प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग बीस साल पहले पूरे महाराष्ट्र सहित गोवा में राजश्री लॉटरी का संचालन वैध तरीके से किया जाता था. सन २०१४ में क्रेंद सरकार द्वारा जी.एस.टी. लागु किए जाने के बाद राजश्री लॉटरी हमेशा के लिए बंद हो गयी .

लेकीन सन २०२२ के फरवरी महिने से महाराष्ट्र के कई बडे शहरों में राजश्री लॉटरी के जैसे हुबहू दिखावा करके गैर कानुनी तरीके से राजश्री लॉटरी की तरह बताकर ऑनलाईन लॉटरी के नाम पर जुआ का अडडा चलाया जा रहा है .वही मुंबई उपनगर में अवैध ऑनलाइन लॉटरी का जाल बडी तेजी से फैल रहा है मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल,

(पेज ५ पर....)

मुंबई में पुलिस पर हमला... जान बचाकर भागे जवान...

मुंबईः अंबीवली इलाके में ईरानी बस्ती में पुलिस की टीम पर भीड़ ने उस समय हमला कर दिया जब वो एक आर-ोपी को पकड़ने वहां पहुंची थी। पुलिस यहां एक हिस्ट्रीशीटर आरोपी को पकड़ने के लिए पहुंची थी। पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया था और अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जा रही थी। तभी भीड़ ने पुलिस की वैन पर पथराव कर दिया और आरोपी को छुड़ा लिया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।

जानकारी के अनुसार, मुंबई के डीएन नगर पुलिस स्टेशन की एक टीम ने 35 आपराधिक मामलों में आरोपी फिरोज खान की पहचान की थी। 10 अगस्त को पुलिस अधिकारी के रूप में लोगों के एक समूह द्वारा एक व्यक्ति को कथित रूप से ठगा गया था। उस मामले में भी फिरोज शामिल था। धोखाधड़ी के मामले में उसकी पहचान के बाद, पुलिस दल के कुछ सदस्य ईरानी बस्ती पहुंचे। पुलिस को फिरोज खान एक सैलून में मिला। जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस के अन्य सदस्यों को सतर्क कर दिया गया। पुलिस के बाकी सदस्य मौके पर पहुंचे और फिरोज खान को हिरासत में ले लिया। जैसे ही पुलिस टीम ने एक वैन में ईरानी बस्ती से बाहर निकलना शुरू किया, उस इलाके में भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने पुलिस की टीम पर पथराव करना शुरू कर दिया। हमला तब तक जारी रहा जब तक कि पुलिस आरोपी को इलाके से बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो गई।

यह पहली बार नहीं है जब ईरानी बस्ती के स्थानीय लोगों ने पुलिस पर हमला किया है। अप्रैल 2017 में भी 25 लोगों की भीड़ ने पुलिसक र्मियों की एक टीम पर हमला किया था। एक पुलिसकर्मी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की कोशिश भी की गई थी। तब पुलिस एक चेन स्नैचर को पकड़ने के लिए ईरानी बस्ती में गई थी।

संपादकीय

मराठा आरक्षण पर 'हल्ला बोल'

महाराष्ट्र का एक हिस्सा मराठा आरक्षण की आग में झुलस रहा है. आंदोलन जारी है. कुछ लोगों का कहना है कि मराठा आरक्षण पर 'सियासी पर्यटन' हो रहा है. इस मामले को लेकर आज सीएम एकनाथ शिंदे ने अहम बैठक बुलाई. वहीं आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे जालना पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात के बाद लोगों को संयम बरतने की अपील की है. राज ठाकरे ने कहा, 'इस मामले में मुझे कुछ बातें बताई गई हैं इसलिए मैं जल्द से जल्द मुख्यमंत्री से मुलाकात करूंगा. इस मामले को किस तरह सिर्फ देखा जा रहा है मैं अभी इस बारे में आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता. मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल सकता. मैं आपको कोई झूठी आशा नहीं दिखाने वाला, ये मैं नहीं कर सकता.'

अपने संबोधन में राज ठाकरे ने कहा, 'इस मामले को लेकर वो सीएम शिंदे से बात करेंगे. राजनेता आप पर ध्यान नहीं देंगे. मैं अभी लोगों को बता रहा था, मराठा समाज को आरक्षण मिलने वाला नहीं है, यह सभी राजनेता आपका का उपयोग कर लेंगे, लेकिन आप पर ध्यान नहीं देंगे. मराठा आरक्षण का मुद्दा अभी कोर्ट में है, आप इस बात को भी समझिए. यह आपको आरक्षण की लालच दिखाकर इस पक्ष से उसे पक्ष में..सत्ता में आने के बाद आप पर ही गोलियां चलाएंगे. आप इसके लिए पुलिस को दोष मत दीजिए, पुलिस को जिसने आदेश दिया उसे दोष दो. पुलिस क्या करेगी ये तो आपके और मेरे जैसी है,'

राज ठाकरे ने कहा, 'समंदर में छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला खड़ा करेंगे इसी पुतले के नाम पर आपका वोट मांगा गया था. 2007 या 2008 में यह विषय उठा था. ये लोग पुतले के नाम पर आरक्षण के नाम पर आपका वोट ले लेंगे और सत्ता में आने के बाद आपको छोड़ देंगे. मैं आज आप लोगों के सामने विनती करने आया हूं. देवेंद्र फडणवीस ने कहा इस मुद्दे को लेकर राजनीति मत करिए अरे वाह! अगर विरोधी पक्ष में होते तो यही राजनिति करते. जिस तरह का वीडियो मैंने देखा, जिस तरह से मेरे माताओं-बहनों के ऊपर लाठियां चल रही थी. ऐसे लोगों के लिए जान जोखिम में मत डालिए उन्हें फर्क नहीं पड़ता लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है आज कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है. लेकिन जब होगा तब वह फिर ऐसा ही कोई मुद्दा लेकर आपके सामने आएंगे. आरक्षण के मुद्दे पर कई जिलों में तनाव है. जालना समेत कई जिलों मे बस सेवा बंद है. जालना हिंसा मामले में 50 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई हैं. एसपी पर गाज गिराते हुए उन्हें छुट्टी पर भेजा गया है. ऐसे में सरकार, पुलिस प्रशासन सभी लोगों से शांति बरतने की अपील कर रहे हैं.

सत्य का क्षरण: राजनीतिक समाचारों से जुड़ा कलंक और पत्रकारिता पर इसका प्रभाव

सूचना अधिभार और तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण के प्रभुत्व वाले युग में, पत्रकारिता के परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। दुर्भाग्य से, एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति सामने आई है: राजनीतिक समाचार पत्रकारिता के क्षेत्र में एक कलंक बन गए हैं। इस घटना की विशेषता उन पत्रकारों की निरंतर जांच है जो राजनीतिक मामलों पर सच्चाई से रिपोर्ट करते हैं, जिसमें प्रत्येक पक्ष दूसरे पर पक्षपात करने और तथ्यों को विकृत करने का आरोप लगाता है। यह लेख इस परेशान करने वाली प्रवृत्ति की उत्पत्ति और परिणामों पर प्रकाश डालता है, पत्रकारों, समग्र रूप से पत्रकारिता और अंततः जनता पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों की खोज करता है।

ध्रुवीकरण का उदय और पत्रकारिता पर इसका प्रभाव

राजनीतिक समाचारों में मौजूदा संकट की जड़ें समाज के बढ़ते ध्रुवीकरण में छिपी हैं। जैसे-जैसे वैचारिक विभाजन गहराता जा रहा है, व्यक्ति अपने विश्वासों में और अधिक मजबूत होते जा रहे हैं और ऐसे समाचार स्रोतों की तलाश कर रहे हैं जो उनके पहले से मौजूद पूर्वाग्रहों से मेल खाते हों। यह घटना, जिसे आमतौर पर ''पुष्टिकरण पूर्वाग्रह'' के रूप में जाना जाता है, ने प्रतिध्वनि कक्षों और फिल्टर बुलबुले का निर्माण किया है, जहां लोग समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से घिरे होते हैं और असहमतिपूर्ण दृष्टिकोण से बचाए जाते हैं।

''पत्रकार सत्य की खोज में अपनी स्वतंत्रता और अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं, फिर भी सराहना के बजाय, उन्हें अक्सर संदेह और संदेह का सामना करना पड़ता है, जो समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को कमजोर करने का एक रणनीतिक कदम है।''

बदले में, पत्रकार अक्सर इस विभाजनकारी परिदृश्य की गोलीबारी में फंस जाते हैं। राजनीतिक मामलों पर रिपोर्टिंग करते समय, उन्हें अपने लक्षित दर्शकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भारी दबाव का सामना करना पड़ता है। यदि कोई पत्रकार एक सच्चा विवरण प्रस्तुत करता है जो एक पक्ष की पूर्वकल्पित धारणाओं को चुनौती देता है, तो उन पर पक्षपात का आरोप लगने या यहां तक कि व्यक्तिगत हमलों का सामना करने का जोखिम होता है। यह दमघोंटू माहौल पत्रकारिता की अखंडता के लिए हानिकारक है और इसके मूल उद्देश्य को कमजोर करता है: जनता को सटीक और निष्पक्ष जानकारी प्रदान करना।

धारणा समस्या: पत्रकारों, पत्रकारिता और जनता के लिए एक नुकसान

राजनीतिक समाचारों से जुड़े कलंक का प्रभाव कई हितधारकों के लिए कई गुना और हानिकारक है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह पत्रकारों को अपने पेशे को ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ आगे बढ़ाने से हतोत्साहित करता है। प्रतिशोध का डर या जनता का विश्वास खोने से पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों से समझौता करते हुए आत्म-सेंसरशिप हो सकती है। यदि पत्रकारों को विवादास्पद राजनीतिक मुद्दों पर सटीक रिपोर्टिंग करने से हतोत्साहित किया जाता है, तो जनता सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक वस्तुनिष्ठ जानकारी तक पहुंच खो देती है।

''पत्रकार, अपनी अमूल्य सेवा के बावजूद, खुद को आलोचना और जांच का निशाना पाते हैं, भले ही उनका नाम अमीरों और शक्तिशाली लोगों की सूची से गायब हो।''

इसके अलावा, यह प्रवृत्ति मीडिया में जनता के विश्वास को कम करती है। जब लोग मानते हैं कि पत्रकार पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण पूर्वाग्रहों से प्रेरित होते हैं, तो समग्र रूप से पत्रकारिता की विश्वसनीयता कम हो जाती है। ऐसे युग में जहां गलत सूचना और दुष्प्रचार बड़े पैमाने पर होता है, विश्वास की यह हानि समाज को और अधिक खंडित करती है, जिससे आम जमीन स्थापित करना और रचनात्मक बातचीत में शामिल होना कठिन हो जाता है।

जिम्मेदारी की भूमिका: ईमानदार पत्रकारिता को पहचानना और उसका समर्थन करना

संदेह और अविश्वास की संस्कृति को कायम रखने के बजाय, उन पत्रकारों की पहचान करना और उनका समर्थन करना महत्वपूर्ण है जो सच्चाई और ईमानदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। पत्रकारिता की अखंडता और पेशेवर नैतिकता के पालन का जश्न मनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये गुण विश्वसनीय और जवाबदेह रिपोर्टिंग का आधार बनते हैं। पत्रकारों के प्रयासों को मान्यता देकर, जो आख्यानों पर तथ्यों को प्राथमिकता देते हैं, समाज एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा दे सकता है जो जिम्मेदार पत्रकारिता को प्रोत्साहित करता है और उद्देश्यपूर्ण जानकारी के प्रसार को बढ़ावा देता है।

''जिम्मेदार पत्रकारिता पत्रकारों और जनता दोनों से सामूहिक प्रयास की मांग करती है। सत्य के प्रति प्रतिबद्ध पत्रकारों का समर्थन करके और कई दृष्टिकोणों से जानकारी का मूल्यांकन करके, हम विभाजन को पाट सकते हैं और उद्देश्यपूर्ण रिपोर्टिंग के माहौल को बढ़ावा दे सकते हैं।''

इसके अलावा, राजनीतिक समाचारों से जुड़े कलंक से निपटने में समाचार उपभोक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। केवल पूर्वकल्पित धारणाओं की पुष्टि करने वाले स्रोतों पर निर्भर रहने के बजाय, आलोचनात्मक सोच में संलग्न होना और कई दृष्टिकोणों से जानकारी का मूल्यांकन करना अनिवार्य है। विविध दृष्टिकोणों की तलाश करके और सम्मानजनक प्रवचन में शामिल होकर, व्यक्ति ध्रुवीकरण के प्रभाव को कम कर सकते हैं और एक स्वस्थ सूचना पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दे सकते हैं।

जो लोग पत्रकारों पर पक्षपात करने और बाहरी प्रभावों से आसानी से प्रभावित होने का आरोप लगाते हैं, उनके लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे उन महत्वपूर्ण जोखिमों को भी याद रखें जिनका सामना पत्रकारों को अपना काम करने में करना पड़ता है। पत्रकारिता एक खतरनाक पेशा हो सकता है, दुनिया भर के पत्रकार सच्चाई को उजागर करने और जवाबदेह होने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। सत्य का साहसपूर्ण अनुसरण करने के कारण कई पत्रकारों को उत्पीड़न, शारीरिक हमलों और यहां तक कि हत्या का भी सामना करना पड़ा है। हिंसा के ये कृत्य न केवल समाज से मूल्यवान आवाजों को छीनते हैं बल्कि भय और धमकी का माहौल भी बनाते हैं जो सूचना के मुक्त प्रवाह को बाधित करता है। सत्य की निरंतर खोज में पत्रकारों द्वारा किए गए बलिदानों को स्वीकार करना और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने और जनता के सूचना प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानना आवश्यक है।

कुल मिलाकर यह कह सकते है कि आज के दौर में राजनीतिक समाचारों से जुड़ा कलंक पत्रकारों, पत्रकारिता और जनता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। जैसे-जैसे वैचारिक विभाजन गहराता जा रहा है और पुष्टिकरण पूर्वाग्रह पनप रहा है, पत्रकार खुद को विश्वसनीयता की निरंतर लड़ाई के बीच में पाते हैं। हालाँकि, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि पत्रकारिता स्वाभाविक रूप से पक्षपाती नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो जनता को सूचित करने और सशक्त बनाने का कार्य करता है।

एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देकर जो सत्य और अखंडता को महत्व देता है, इन सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध पत्रकारों का समर्थन करता है, और सक्रिय रूप से जिम्मेदार समाचार उपभोग में संलग्न होकर, हम इस कलंक के हानिकारक प्रभावों का प्रतिकार करना शुरू कर सकते हैं और राजनीतिक पत्रकारिता में विश्वास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। केवल ऐसा करके ही हम सूचित सार्वजनिक चर्चा और अधिक एकजुट समाज को सुविधाजनक बनाने में पत्रकारिता की आवश्यक भूमिका को बहाल कर सकते हैं।

दरियादिली: कौन हैं 6000 करोड़ की संपत्ति दान करने वाले त्यागराजन? उनकी कंपनी बिना CIBIL देखे देती है लोन

आर त्यागराजन श्रीराम समूह के संस्थापक हैं। उनका जन्म 25 अगस्त, 1937 को चेन्नई (तत्कालीन मद्रास) में हुआ था। उन्होंने अप्रैल, 1974 में श्रीराम समूह की नींव डाली थी। उनके साथ सहसंस्थापक के रूप में एवीएस राजा और टी. जयरामन भी जुड़े थे।

श्रीराम समूह के संस्थापक राममूर्ति त्यागराजन ने अपनी 6000 करोड़ रुपए से अधिक की सर्पत्ति दान में देने का फैसला किया है। उन्होंने अपने लिए सिर्फ एक छोटा सा घर और 5 हजार डॉलर (4 लाख रुपए) की कार को छोड़कर अपनी लगभग सारी संपत्ति अपने कर्मचारियों के लिए बने ट्रस्ट में देने का एलान कर दिया है। 86 साल के त्यागराजन ने एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में कहा, ''मैंने 750 मिलियन डॉलर (करीब 6,210 करोड़ रुपए) की संपत्ति दान कर दी है।'' हालांकि, उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि उन्होंने संपत्ति कब दान की है।

एक साक्षात्कार में त्यागराजन ने कहा- मैं थोड़ा वामपंथी हूं, लेकिन मैं उन लोगों की जिंदगी से कुछ थोड़ी परेशानी कम करना चाहता हूं, जो संघर्ष कर रहे हैं। त्यागराजन ने ये भी कहा कि मैं वित्तीय सेवाओं के कारोबार में ये साबित करने के लिए आया हूं कि बिना क्रेडिट हिस्ट्री और रेगुलर इनकम वाले लोगों को भी लोन देना उतना

जोखिम भरा नहीं है, जितना आमतौर पर समझा जाता है।

बिना क्रेडिट हिस्ट्री देखे ऋण मुहैया कराता है श्रीराम ग्रुप

त्यागराजन ने कहा कि गरीबों को लोन देना समाजवाद का ही एक हिस्सा है। हम कोशिश करते हैं कि लोगों को कम से कम दरों पर लोन मुहैया कराया जाए। त्यागराजन ने कहा कि हमारा ग्रुप लोन देते समय कभी भी ये नहीं देखता कि ऋण लेने वाले का क्रेडिट स्कोर क्या है? रिपोर्ट्स के अनुसार श्रीराम समूह लोन देने से पहले ग्राहकों का उक्कक्छ नहीं चेक नहीं करता है।

1937 में पैदा हुए, 1974 में शुरू की कंपनी

आर त्यागराजन श्रीराम समूह के संस्थापक हैं। उनका जन्म 25 अगस्त, 1937 को चेन्नई (तत्कालीन मद्रास) में हुआ था। उन्होंने अप्रैल, 1974 में श्रीराम समूह की नींव डाली थी। उनके साथ सहसंस्थापक के रूप में एवीएस राजा और टी. जयरामन भी जुड़े थे। शुरूआती दौर में समूह बतौर चिटफंड कंपनी काम करता था, लेकिन धीरे-धीरे कंपनी ने ऋण और बीमा कारोबार में भी कदम रख दिया। श्रीराम फाइनेंस भारत की प्रमुख नन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। श्रीराम समूह कई तरह के ऋण और बीमा से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराता है। वर्ष 2013 में भारत सरकार की ओर से त्यागराजन को पद्मभूषण नवाजा गया था।

श्रीराम समूह में एक लाख से अधिक लोग करते हैं काम

वर्तमान में श्रीराम समूह में 1 लाख 8 हजार कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसकी सबसिडरी कंपनियों में श्रीराम फाइनेंस, श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस, श्रीराम इनसाइट, श्रीराम फॉर्च्यून, श्रीराम एएमसी, श्रीराम वेल्थ और श्रीराम प्रॉपर्टीज शामिल हैं। त्यागराजन का कहना है कि वे बाजार की तुलना में अपने कर्मियों को कम पैसे देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अपने आसपास के लोगों से पैसे के मामले में प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। एक व्यक्ति के तौर पर यह सही नहीं होता है। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए जिससे आपकी सारी जरूरतें ठीक से पूरी हो सके।

हमारे खून से पाई है, तुमने आजादी... हमीं से पूछते हो तुम, हमारा हक क्या है?

जिसने बाबर के खिलाफ सन 1527 के खानवा की लडाई में राणा सांगा के साथ मिलकर लडाई लड़ी जिसमे राजा हसन खान मेवाती अपने 12,000 सैनिकों के साथ शहीद भी हुए किन्तु अपने अखंड भारत देश से बफादारी के बीच अपने धर्म को आडे नहीं आने दिया' इसके बाद भी मुगलों द्वारा मेवाती राजाओं को हजारों बार सत्ता का लालच दिये जाने के बावजूद उन्होने कभी भी #मुगलों की गुलामी कुबूल नहीं की,

इसलिये हमेशा बागी कहलाये गये और सत्ता से सोशित और वांचित रहे ''

जिनके बड़े बुजुर्गों ने छत्रपति शिवाजी माहाराज को औरांगजेब की कैद से आगरा के किले से छुडवाया था '

जिसने 1857 की क्रांती में ब्रिटिशों की नाक में दम कर दिया जिसके बदले में अंग्रेजों द्वारा मेवातियों के 10,000 क्रांतिकारियों को फांसी पर चढा दिया गया'

इससे बड़ी शहादत किसी और तारीख में नहीं मिलती '' इस कारण अंग्रेजों ने भी इन्हें हमेशा

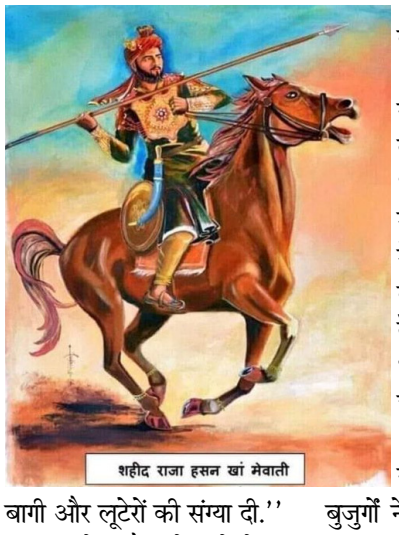

शहीद राजा हसन खां मेवाती

बागी और लूटेरों की संग्या दी.''

जिसके खौफ से अंग्रेजों की अनेकों बटालियन चौबीस घंटे सिर्फ हरियाणा/ राजस्थान उत्तर प्रदेश के #मेवात की तरफ ही तेनात रहती थी '

जिससे ली हुई जमीन पर संसद भवन की इमारत, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन और #दिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण लूटियन जोन बना हे ''

जिसके स्वतांत्रता संग्राम मे कुर्बान हुए शाहीदों के नाम आज भी इन्डिया गेट पर सबसे बड़ी तादात में हें ''

जिनके बारे में 1947 संग्राम में महात्मा गांधी ने कहा था की मेवाती/ मेव भारत की रीड़ हें'' एवं महात्मा गांधी ने 1947 में भारत पकिस्तान के बटवारे के समय अनशन के लिये मेवात के पवित्र धरती के घासेडा गॉव को चुना ''

(मेवाती मुस्लिम राजपूतों) हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस देश की एक एक इंच मिट्टी की खातिर कई बार कुर्बानियां दी हैं, पर अफसोस आज कुछ लोगों को हमारे भारतवासी और देशभक्त होने का सबूत देना पढ़ेगा '' क्या इसी दिन के लिये हमारे बुजुर्गों ने लाखों कुर्बानियां दी थीं..?

शायद मेरी ये पोस्ट कई लोगों के दिमाग पर पड़ी धूल छांटने में कामयाब रहेगी '

'मैं माफी मांगता हूं': बॉम्बे हाईकोर्ट के जज ने भरी अदालत में किया इस्तीफे का ऐलान

नागपुरः बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस रोहित बी देव ने खुली अदालत में चौंकाने वाला कदम उठाते हुए अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया. जस्टिस रोहित देव ने अदालत में मौजूद लोगों से कहा, ''अगर मेरी किसी बात से किसी को ठेस पहुंची है, तो इसके लिए माफी मांगता हूं. लेकिन मैं अपने आत्मसम्मान के खिलाफ काम नहीं कर सकता.'' हालांकि, उन्होंने इस्तीफा देने के पीछे का कारण नहीं बताया.

इस्तीफे के ऐलान के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जस्टिस देव ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से पद छोड़ दिया है. अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया है.

जस्टिस देव को जून 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया था. वह दिसंबर 2025 में रिटायर होने वाले थे. जज बनने से पहले वो एडवोकेट जनरल थे.

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में बैठने वाले जस्टिस देव ने साल 2022 में माओवादी लिंक मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा को बरी कर सुर्खियां बटोरी थीं. उन्होंने जीएन साईबाबा को बरी करते हुए उनपर लगे आजीवन कारावास को भी रद्द कर दिया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस फैसले को निलंबित कर दिया और हाई कोर्ट की नागपुर बेंच को मामले की नए सिरे से सुनवाई करने का आदेश दिया था.

पिछले हफ्ते, जस्टिस देव ने 3 जनवरी के महाराष्ट्र सरकार के संकल्प (आदेश) के संचालन पर रोक लगा दी थी. इस आदेश के जरिए राज्य को निर्माण में लगे ठेकेदारों द्वारा गौण खनिजों की अवैध खुदाई से संबंधित दंडात्मक कार्यवाही को रद्द करने का अधिकार दिया गया था.

महाराष्ट्र क्राईम्स
मुंबई, 05 सितंबर, 2023

मुंबईः सेना से कोर्ट मार्शल के बाद बनाई फर्जी प्रोफाइल और 7 महिलाओं से की शादी, पाकिस्तान जाकर ली ट्रेनिंग

मुंबईः कोर्ट मार्शल के बाद बनाई फर्जी प्रोफाइल और 7 महिलाओं से की शादी, पाकिस्तान जाकर ली ट्रेनिंग महाराष्ट्र के नवी मुंबई से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसका सेना से कोर्ट मार्शल हो चुका है और यह शख्स खुद को आर्मी अफसर बताकर सात महिलाओं से शादी कर चुका है. इस शख्स के पास से पुलिस को संदिग्ध दस्तावेज भी मिले हैं.

महाराष्ट्र के नवी मुंबई से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. आर्मी से निकाले गए चौधरी नाम के शख्स को खारघर पुलिस ने गिरफ्तार कर

लिया है. चौधरी खुद को आर्मी का बड़ा अधिकारी बताकर पहले 7 महिलाओं से शादी कर चुका है. 2017 मैं आर्मी ने चौधरी का कोर्ट मार्शल करके निकाल दिया था.

कोर्ट मार्शल के बाद गई नौकरी

आर्मी में चौधरी सिपाही के पद पर कार्यरत था, लेकिन साल भर से अपने ड्यूटी पर नहीं गया था और बिना किसी को बताए वह अचानक गायब हो गया था. इसके बाद विभाग द्वारा उससे कई बार संपर्क किया गया लेकिन इसके बावजूद भी उससे संपर्क नहीं हो सका, जिसकी वजह से आर्मी ने 2017 में उसका कोर्ट मार्शल कर दिया था.

क्या रात भर ON रहता है घर में लगे WiFi का राउटर?

सब काम छोड़कर आज ही जान लें इसकी सच्चाई

अगर आप घर में इस्तेमाल होने वाले वाईफाई को रात में चलता हुआ छोड़ देते हैं तो आपको शायद उसके बारे में जानकारी नहीं है. ज्यादातर

लोगों के घरों में ऐसा ही होता है जो वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं. लोग वाईफाई का इस्तेमाल करने के बाद इसे ऑफ करना भूल जाते हैं या फिर उन्हें पता ही नहीं है कि वाईफाई को ऑफ भी किया जाता है. अगर आपके घर में भी वाईफाई लगा हुआ है और आप इसका राउटर बिना स्विच ऑफ किए हुए रात में सोने चले जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यह कितना खतरनाक साबित हो सकता है. ऐसे मैं आज हम आपको विस्तार से इसके बारे में बताने जा रहे हैं.

इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से शरीर में होने वाली बीमारियों से अगर आप खुद को बचाए रखना चाहते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि एक बार इस्तेमाल खत्म होने के बाद वाईफाई राउटर को बंद कर देना चाहिए. लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं होती लेकिन ऐसा असल में होता है ऐसे में आपको आगे से सावधानी बरतनी चाहिए.

इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से शरीर में कुछ ऐसी बीमारियां जन्म ले सकते हैं जो बेहद ही खतरनाक है और इनसे आपका शरीर बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है.

अगर आपके घर में वाईफाई राउटर रात भर चलता रहता है तो इससे निकलने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से कुछ समय बाद आपके शरीर में कई बीमारियां जन्म ले सकती हैं. ऐसा राउटर से निकलने वाले रेडिएशन की वजह से होता है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी होती ही नहीं है.

लंबे समय तक अगर घर में रात के समय पर वाईफाई राउटर चलता रहता है तो इससे जिस स्थान पर वाईफाई राउटर लगा है वहां पर रात में सोने वाले शख्स को इनसोम्निया की समस्या हो सकती है जिसमें शख्स को नींद नहीं आती है और उसे दवाई लेने की जरूरत पड़ती है. नींद ना आने की यह समस्या आगे चलकर काफी गंभीर हो सकती है ऐसे में आज हम आपको रात के समय में वाईफाई राउटर बंद कर देना चाहिए.

वाईफाई राउटर अगर रात भर चलता रहता है तो इससे कई तरह की समस्याएं हो सकती है. दरअसल वाईफाई राउटर चलने से जो रेडिएशन निकलता है वह आपकी नींद को प्रभावित कर सकता है. जिस घर में रात भर वाईफाई चलता रहता है वहां पर कई सारे सदस्यों को नींद से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं.

किसी व्यक्ति के चले जाने के बाद उसके लोन का क्या होगा, जानिये बैंक किससे करेगा रिकवरी

बैंक या अन्य संस्थानों में लोन लेने वाले शख्स की मृत्यु के बाद इसक भुगतान किस तरह से होगा ये ज्यादातर लोन की कैटेगरी पर निर्भर करता है. होम लोन में इसके नियम अलग होते

हैं तो पर्सनल लोन के लिए अलग तरह से कार्यवाही की जाती है. जानकारों के अनुसार जहां होम लोन और ऑटो लोन के मामलों में रिकवरी करना आसान होता है वहीं पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन के केस में रिकवरी करना थोड़ा कठिन होता है.

इसलिए आपको हर लोन के हिसाब से समझना होगा कि लोन वाले शख्स की मृत्यु के बाद लोन का भुगतान कौन करता है? आइए जानते हैं मृत्यु के बाद लोन से जुड़े नियम क्या हैं और किस तरह इसका भुगतान किया जा सकता है.

होम लोन की अवधि आम तौर पर लंबी होती है. बैंक ये लोन देते वक्त इसका ढांचा इस तरह का रखते हैं कि लोन लेने वाले व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु के बाद भी रिकवरी पर कोई असर नहीं पड़ता है. इस तरह के ज्यादातर मामलों में को-एप्लिकेंट का प्रावधान भी रहता है जो लोन लेने वाले व्यक्ति के परिवार का ही कोई सदस्य होता है. लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद इसके भुगतान की जिम्मेदारी को-एप्लिकेंट की ही होती है.

इसके अलावा कई बैंकों में लोन लेते वक्त ही एक इंश्योरेंस करवा दिया जाता है और अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बैंक इंश्योरेंस के माध्यम से इसे वसूल लेता है. इसलिए जब भी आप लोन लेते हैं तो आप बैंक से इस इंश्योरेंस के बारे में पूछ सकते हैं. इसके अलावा उन्हें ऑप्शन दिया जाता है कि वो संपत्ति बेचकर लोन का भुगतान करें. अगर ऐसे भी नहीं होता है तो बैंक रंशी२ एक्ट के तहत लोन के एवज में रखी गई संपत्ति को नीलाम कर देता है और इससे लोन की बकाया राशि वसूल लेता है. पर्सनल लोन की बात करें तो ये सुरक्षित लोन नहीं होते हैं और इन्हें अनसेक्युर्ड लोन की कैटेगरी में रखा जाता है. पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन की स्थिति में मृत्यु हो जाने के बाद बैंक किसी दूसरे व्यक्ति से पैसे नहीं वसूल कर सकते हैं. साथ ही उत्तराधिकारी या कानूनी वारिस को भी इस लोन को चुकाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. ऐसे में व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही इस लोन को राइट ऑफ कर दिया जाता है यानी बट्टा खाते में डाल दिया जाता है. ऑटो लोन एक तरह से सिक्योर्ड लोन होता है. अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बैंक सबसे पहले घर वालों से संपर्क करता है और उनसे बकाया लोन का भुगतान करने के लिए कहता है. अगर मृतक व्यक्ति का परिवार इसके लिए राजी नहीं होता है तो कम्पनी गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर उसकी नीलामी के जरिये अपनी बकाया रकम वसूल सकती है.

महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाईन लॉटरी पर

(पेज १ का शेष....)

भिवंडी, कल्याण आदि शहरों में बडे पैमाने पर यह कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसा लगता है कि, लॉटरी माफियाओं को पुलिस कार्यवाही का कोई डर नहीं रहा. ऑनलाइन लॉटरी की लत के कारण कई लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है.

साथ ही इस अवैध लॉटरी से भले ही राज्य और केंद्र सरकार को करोडों के राजस्व का नुकसान हो रहा हो, लेकिन लॉटरी माफियाओं के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया जा रहा है. वही राज्य सरकार के राजस्व विभाग की हानि के साथ-साथ स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों के जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड रहा है . राज्य सरकार ने महाराष्ट्र मुंबई सहित ऑनलाइन लॉटरी कारोबार पर पूरी तरह रोक लगा दी है. लेकिन कुछ लॉटरी माफिया बिना कानून के डर के इस धंधे को चला रहे हैं. अवैध ऑनलाइन लॉटरी माफिया महाराष्ट्र सहित मुंबई और भारत के लोगों से अरबों रुपये लूट रहे हैं। चूंकि इन अवैध लॉटरी माफियाओं के खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही नहीं की जा रही है और उन्हें अदालतों से तुरंत जमानत मिल रही है, इसलिए लॉटरी का यह कारोबार बढने लगा है। नासिक जिला पुलिस आयुक्त ने महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र भेजकर लॉटरी माफियाओं के खिलाफ एमपीडीए और मकोका के तहत कार्यवाही की अनुशंसा की है. और सभी अवैध लॉटरी संचालकों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है. इससे अनेक लोगों के पारिवारिक जीवन बर्बाद हो रहे है. बताया जा रहा है कि बहुत से लोगों ने अवैध ऑनलाइन लॉटरी में भारी मात्रा में पैसा खोने के बाद आत्महत्या कर ली है. कई स्कूली बच्चेऔर कॉलेज के छात्र बिना स्कूल और कॉलेज जाए ऑनलाइन लॉटरी खेल रहे हैं. प्लेटिनम, जीसी कूपन, कौशल गेम, गोल्डन लकी कूपन, स्कील, एमएस लकी कूपन, जिसे फन गेम के नाम से भी जाना जाता है, कैसीनो

रोलेट सिटी, लूडो मास्टर, किशोर पट्टी लूडो , लोटस जैसी लॉटरी खेल कर लोग अपना जीवन बर्बाद कर रहे है . वहि मुंबई के लोग इस बात से हैरान हैं कि लॉटरी माफिया के खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है?

आप को बता दे कि इस समाचार पत्र नें मुंबई के आर.सी. एफ. पुलिस थाना क्षेत्र में जब इन अवैध लॉटरी के खिलाफ सर्वे किया तो. इन जगहों पर यह करोबार खुलेआम चलता पाया.

१) दुकान नं.४ एम.एस.बिल्डींग नं.१७ नित्यानंद बाग रोड आर. सी. मार्ग .चेंबुर मुंबई नं. ७४. २) बिल्डींग नं.६ के सामने , के .जी. एन. चायनिस कार्नर के बाजु में चेंबुर कैंप चेंबुर कॉलोनी चेंबुर मुंबई नं. ७४. ३) दुकान नं. २ बी.जे.पी. कार्यालय के पीछे वासवानी बुक स्टोर के पास डॉ. सी. जी.रोड जय जलाराम बुक स्टोर के बाजु में चेंबुर कॉलोनी मुंबई ७४ .४) दुकान न. ३ साबरी शिवम के सामने नित्यानंद बाग रोड ड्रीम्स प्रॉपर्टी के बगल में चेंबुर मुंबई ४७. ५) दुकान नं. ३ सी. आर. सी.मार्ग सफल गंगा के पास शगुन लॉन के सामने आर.सी.मार्ग चेंबुर कॉलोनी मुंबई नं. ७४ ६) दुकान नं. २ एस.वी.पी.नगर मच्छी मार्केट के सामने, वाशिनाका ब्रिज के पास चेंबुर मुंबई नं.७४. ७) आशिष सिनेमा के पास लक्ष्मी कॉलोनी मरोल चर्च के सामने माहुल रोड चेंबुर मुंबई ४७.

इस विषय को लेकर २१ जुन २०२३ को अपर पुलिस आयुक्त , पुर्व प्रादेशिक विभाग पुलिस उपायुक्त परिमंडल क्रमांक 6, सहायक पुलिस आयुक्त ट्राम्बे विभाग, इसी के साथ आरसीएफ पुलिस थाने को जांच करने के लिए लिखीत पत्र दिया गया. वही स्थानिय आर.सी.ए. पुलिस थाने को २१ जुन के रोज शिकायत पत्र देने गए हमारे प्रतिनीधी को अमलदार कक्ष में मौजुद पुलिस उप निरीक्षक रमेश खोपले ने लेटर ना लेते हुए वापस लौटा दिया. समाचार पत्र के संपादक ने जब २१ जुन को वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मुरलीधर करपे को वॉट्सएप

पर लेटर न लेना का मैसेज भेजा, इस पर मुरलीधर करपे ने पत्र वापस भेजने को कहा।

दिनांक २२ अगस्त 2023 को लेटर ले लिया लेकीन इस विषय पर कोई भी कार्यवाही ना करते हुए गुंडो को घर का पता दे दिया. इससे साफ जाहिर होता है कि वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के जानकारी में यह सभी अवैध लॉटरीयों का करोबार चल रहा है. १८ तारीख के रोज रात के ९ बजे के आसपास कुछ अज्ञात गुंडे घर पर आ गए और परिवार को डराकर धमकी दी, और कहां कि सिराज चौधरी को शांत रहने कहो नही तो बहुत कुछ हो सकता है . जब संपादक को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी और परिवार की सुरक्षा के लिए लेटर लिखकर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को वॉटसेप किया . दुसरे दिन १९ तारीख को आर. सी.एफ. पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक रविंद्र मोहिते (कानुन एवं सुव्यवस्था) ने लेटर देकर पुलिस थाने में स्टेटमेंट के लिए बुलाया. प्रश्न यह है कि जब हमने लिखित रूप में सारी जानकारी दी है तो हमें पत्र भेज कर जवाब लेने के लिए क्यों बुलाया जा रहा है? जवाब लेना एक बहाना है यह सिर्फ शिकायतकर्ता को परेशान करने का तरीका है. हां जब शिकायत की गई दुकान पुलिस को यदि नहीं मिलती और पुलिस हमें बुलाए तो बात समझ में आती है.

इस प्रकार से प्रताडित करने से साफ जाहिर होता है की स्थानिय पुलिस थाने का आशीर्वाद इन लॉटरी माफिया को प्राप्त है. एक पत्रकारऔर संपादक का फर्ज होता है, समाज में हो रही बुराईयों को उजागर करके प्रशासन तक पहुंचाना, लेकिन गुंडो को भेज कर पत्रकार के परिवार के साथ जान से मारने की योजना बनाने वाले आर.सी.एफ.पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मुरलीधर करपे पर कानुनी कार्रवाइ होना आवश्यक है. जल्द ही पत्रकारों का एक शिष्ठ मंडल इस बात को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा.

वही महाराष्ट्र क्राईम्स के संपादक ने राज्य के पुलिस लिस महासंचालक और गृह सचिव और पुलिस आयुक्त से वरीष्ठ पुलिस निरीक्षक मुरलीधर करपे के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है.

चंडीगढ़ पुलिस के सब-इंस्पेक्टर ने लूटे 1 करोड़: कारोबारी को किडनैप कर लूटा; 75 लाख रुपए बरामद, नवीन फोगाट दूसरी बार नौकरी से बर्खास्त

चंडीगढ़ पुलिस के सब-इंस्पेक्टर और उसके साथी पुलिसकर्मियों द्वारा कारोबारी से एक करोड़ रुपए लूट के मामले में पुलिस ने सख्त कार्यवाही की है। मुख्य आरोपी सब-इंस्पेक्टर नवीन फोगाट को दूसरी बार नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। रविवार को चंडीगढ़ की रस्ढ कंवरदीप कौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मामले में 75 लाख रुपए की बरामदगी कर ली गई है लेकिन कोई आरोपी फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी में जुटी है।

इस मामले में 4 अगस्त- शुक्रवार- की देर रात चंडीगढ़ के सेक्टर 39 के थाने में रकनवीन फोगाट के साथ-साथ तीन अज्ञात पुलिसकर्मियों, इमिग्रेशन कंपनी के सर्वेश कौशल, गिल और जितेंद्र नामक शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मामले में कुछ पुलिस अफसरों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। मामले का खुलासा रविवार को हुआ।यह मामला सेक्टर-39 पुलिस थाने से जुड़ा है, जहां के एडिशनल रल्ड की जिम्मेदारी नवीन फोगाट संभाल रहा था। नवीन और उसके साथी पुलिसकर्मियों पर सुनियोजित तरीके से वारदात करने के आरोप हैं। नवीन फोगाट को पहले भी एक मॉडल से रेप करने के केस में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। हाल में वह बहाली हुआ था।

आरोपी रकनवीन फोगाट और उसके साथी पुलिसकर्मियों ने बठिंडा के कारोबारी संजय गोयल से 2-2 हजार रुपए के नोट बदलने के नाम पर एक करोड़ रुपए की लूट की। पुलिसवाले संजय गोयल को किडनैप कर सुनसान जगह ले गए और फिर एनकाउंटर व ड्रग के केस में फंसाकर जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दी। आरोपी रक नवीन फोगाट और अन्य पुलिसकर्मियों पर शुक्रवार देर रात सेक्टर-39 थाने में केस दर्ज कर लिया गया था। मामले में नामजद होने के बावजूद नवीन फोगाट पुलिस अधिकारियों के सामने ही थाने से फरार हो गया। अब पुलिस वारदात में शामिल अन्य पुलिसकर्मियों की पहचान में जुटी है। उधर सेक्टर-39 थाने के रल्ड इंस्पेक्टर नरिंदर पटियाल का कहना है कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। रस्ढ की सुपरविजन में ऊढ

चरणजीत सिंह ही मामले की जांच कर रहे हैं। मामला 4 अगस्त का है। बठिंडा के कारोबारी संजय गोयल ने अपनी शिकायत में कहा कि, उनके दोस्त ने कहा कि कुछ जानकार लोग दो-दो हजार रुपए के नोट बदलना चाहते हैं। इस पर वह 500-500 रुपए के एक हजार नोट लेकर मोहाली पहुंचे और वहां से एयरोसिटी रोड स्थित ब्राइट इमिग्रेशन के दफ्तर चले गए। यहां से सर्वेश नामक शख्स उन्हें लेकर चंडीगढ़ के सेक्टर-40 पहुंचा। संजय गोयल के अनुसार, सेक्टर-40 में एक सब-इंस्पेक्टर पहले से तीन अन्य पुलिसकर्मियों के साथ वर्दी में खड़ा था। उनकी कार रुकते ही सारे पुलिसवाले एकसाथ उसकी गाड़ी में घुस गए और उसे व ड्राइवर को पकड़ लिया। इसी बीच सर्वेश और उसके साथ मौजूद गिल नामक व्यक्ति पुलिस के इशारे पर वहां से निकल गए। इसके बाद पुलिसवालों ने उनकी कार की तलाशी लेकर पैसा निकाल लिया। संजय गोयल ने बताया कि पुलिस टीम कार और पैसे के साथ उसे सेक्टर-40 के बीट बॉक्स पर ले गई। वहां से फिर उसे सेक्टर-39 की धान मंडी के पास ले जाया गया। धान मंडी पहुंचने के बाद उसकी पूरी रकम एक डस्टर कार में रखवाई गई। इसके बाद पुलिस टीम ने उसे पैसा छोड़कर भाग जाने को कहा और ऐसा न करने पर एनकाउंटर करने की धमकी दी। संजय गोयल के अनुसार, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मर्सिडीज कार में कोई बड़ा अफसर भी वहां पहुंचा था लेकिन वह अपनी कार से नीचे नहीं उतरा। इसी बीच पुलिसवालों के कहने पर वह मौके से भाग निकला और घर जाकर परिवार को पूरी वारदात बयां की। इसके बाद मामला रस्ढ कंवरदीप कौर के संज्ञान में लाया गया। एसएसपी के निर्देशों पर चंडीगढ़ के ऊढ चरणजीत ने शिकायतकर्ता संजय गोयल को सेक्टर-39 के थाने बुलाया, जहां उन्होंने रकनवीन फोगाट को पहचान लिया। संजय ने दावा किया कि थाने पहुंचने पर नवीन फोगाट उन्हें बाहर ले जाकर डील की कोशिश करने लगा। जब वह नहीं माने तो नवीन फोगाट थाने से फरार हो गया। उधर देर रात इस संबंध में सेक्टर 39 के पुलिस थाने में रकनवीन फोगाट समेत तीन अज्ञात पुलिसकर्मियों के साथ-साथ इमिग्रेशन कंपनी के सर्वेश कौशल, गिल और जितेंद्र के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। इस मामले में कुछ पुलिस अफसरों की भूमिका की भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है।

आरोपी सब-इंस्पेक्टर नवीन फोगाट पर चंडीगढ़ पुलिस के साइबर सेल में तैनात रहने के दौरान एक मॉडल के साथ रेप का आरोप लगा था। इस केस के बाद उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। अदालत में चली सुनवाई के बाद केस में बरी हो जाने पर उसे हाल ही में चंडीगढ़ पुलिस महकमे में दोबारा ज्वाइन कराया गया था। इसके बाद ही उसे सेक्टर-39 थाने के एडिशनल रल्ड की जिम्मेदारी दी गई थी।

अंग्रेजों ने भूखे मारे 30 लाख भारतीय

कुत्ते-गिद्ध खा रहे थे लाशें; चर्चिल के फैसले से पड़े बंगाल अकाल की कहानी

साल 1943, पश्चिम बंगाल के पश्गुरा थाना का शाहपुरा पोटा गांव। एक बुनकर अपने परिवार को दो वक्त की रोटी तक मुहैया नहीं करा पा रहा था। भूख उसके सिर पर ऐसे सवार हो गई कि वो पागलों की तरह भटकने लगा।

एक दिन उसकी लाश बंगाल की कांसाई नदी में मिली। उसकी पत्नी जब कई दिनों तक अपने 2 बेटों का पेट न भर सकी तो उसने अपने छोटे बेटे को भी कांसाई नदी में बहा दिया।

पूर्वी बंगाल के 30 लाख लोग इसी तरह तड़-प-तड़प कर भूख से मरने के लिए मजबूर हो गए। खेतों में लाशें पड़ी थीं। नदियों में मरे हुए लोगों की लाशें तैर रही थीं। कुत्ते और गिद्ध शवों को नोंच-नोंच कर खा रहे थे।

ऐसा माना जाता है कि भारत में ये सब कुछ उस समय के ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल के एक गलत फैसले की वजह से हुआ।

अंग्रेजों की 'डिनायल पॉलिसी' से बंगाल में हुई भुखमरी की शुरूआत

दिसंबर 1941 में जापानी सेना ने ब्रिटिश उपनिवेश सिंगापुर और बर्मा (म्यांमार) पर कब्जे के लिए हमला किया। अगले 5 महीने तक चली जंग के बाद मई 1942 में जापानी सेना ने दोनों ही जगहों को जीत लिया। इसके बाद जापान की सेना भारत की ओर बढ़ी।

जल्द ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी जापानी सैनिकों ने कब्जा कर लिया। यह माना जाने लगा कि जापान अब बंगाल पर हमला कर देगा। दूसरे विश्वयुद्ध के समय कलकत्ता (कोलकाता) अंग्रेजों के वॉर प्लान का अहम सेंटर हुआ करता था। इसी वजह से ब्रिटिश सेना को जापानी नौसेना के हमले की उम्मीद थी।

ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के चटगांव और मिदनापुर जैसे तटीय इलाकों में 'डिनायल पॉलिसी' लागू कर दी। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों की इसी पॉलिसी की वजह से बंगाल में भुखमरी की शुरूआत हुई थी।

'डिनायल पॉलिसी' के तहत अंग्रेज सैनिक इस इलाके के गांवों में जाकर लोगों के घरों से अतिरि-क्त चावल और नाव जब्त करने लगे। (स्केचः मंसूर नकवी)

इस पॉलिसी के पीछे अंग्रेजों की सोच थी कि जापानी नौसैनिक अगर यहां पहुंचते हैं तो उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पाए। बंगाल के उस समय के सीएम फजलुल हक ने अंग्रेज सरकार की इस पॉलिसी की आलोचना की और 'सबके लिए दाल भात' का नारा दिया।

दूसरी तरफ ब्रिटेन के हजारों-हजार सैनिक कलक-त्ता पहुंच रहे थे। उनके खाने-पीने के लिए बड़ी मात्रा में अनाज की जरूरत थी। अंग्रेज सैनिकों को खाने की किल्लत न हो, इसके लिए अंग्रेज सरकार ने ऐसी नीति तैयार की, जिससे अनाजों की आपूर्ति सैनिक कैंपों और शहरों की ओर हो गई।

इसकी वजह से बंगाल के गांवों में अनाज की कमी पड़ गई। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने केवल उन लोगों तक अनाज पहुंचने दिया, जो युद्ध लड़ने के लिहाज से महत्वपूर्ण थे। गांवों में भूख से मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी।

सरकारी गोदामों में अनाज की कमी न हो, इसके लिए पुलिस लोगों के घरों से चावल जब्त कर ले जाने लगी। इस समय चावल का दाम लगभग आठ और दस गुना तक बढ गया। गांवों के बाजारों में चावल पूरी तरह से खत्म हो गए।

किसानों से जो चावल सरकार और पुलिस नहीं जब्त कर पाई, उसे कारोबारी और कालाबाजारी करने वाले व्यापारी ऊंचे दामों में खरीद ले गए।

इस तरह बड़ी संख्या में लोगों को बगैर कोई खोज-खबर लगे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। परिणाम ये हुआ कि कलकत्ता की सड़कों, पूर्वी बंगाल के गांवों और खेतों में इंसानी लाशें दिखाई देने लगीं।

उस समय के हालात इतने बदतर थे कि इतिहासक-ार माइक डेविस ने अपनी किताब 'लेट विक्टोरियन होलोकॉस्ट' में बंगाल में भूख से मरने वाले लोगों की तुलना नाजी शिविरों और हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम से मरने वाले लोगों से की है।

उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि बंगाल में औपनिवेशिक काल के दौरान भूख से मर रहे लोगों की हालत करीब-करीब 18,000 फुट की ऊंचाई से हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए परमाणु बमों से मरने वाले आम लोगों जैसी ही थी।

अनाज की कमी से नहीं, सरकार के फैसलों से मर रहे थे बंगाल के लोग

'पॉवर्टी एंड फेमिंस' किताब के लेखक और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के मुताबिक 1943 में जब बंगाल में भूख से लोग सड़कों पर मर रहे थे, तब हर इंसान को खिलाने के लिए सरकारी गोदामों में चावल तो काफी था, लेकिन बहुत कम लोगों के पास इस चावल को खरीदने का पैसा था।

16 अक्टूबर 1942 में आए चक्रवात की वजह से मिदनापुर और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया था। समुद्र के किनारे करीब 20 फुट उंची लहरें उठ रही थीं। बंगाल में 225 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही थी।

इस तूफान की वजह से बंगाल में करीब 40 हजार लोगों की मौत हुई। तूफान से किसी तरह बचे लोग अपने घर छोड़ हावड़ा और कलकत्ता जैसे शहरों में जाने के लिए मजबूर हो गए। चक्रवात की वजह से पश्चिम मेदिनीपुर और आस-पास के इलाके में फसलों की पैदावार अच्छी नहीं हो पाई, लेकिन इसके बावजूद बंगाल के दूसरे हिस्सों में 1941 की तुलना में इस साल चावल की अच्छी पैदावार हुई थी।

जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स ने भी अपने रिसर्च पेपर में बताया था कि 1943 में बंगाल का अकाल भारतीय उपमहाद्वीप में एक मात्र ऐसा अकाल था, जो सूखे की वजह से या फसलों के नष्ट होने की वजह से नहीं था।

यह अकाल मानव निर्मित था और अंग्रेज सरकार की गलत नीतियों की देन था। इस साल हाल के सालों की तुलना में बंगाल की मिट्टी में नमी औसत से ज्यादा थी। इसका मतलब ये हुआ कि मिट्टी अनाज की पैदावार करने में सक्षम थी।

चर्चिल का वो एक फैसला, जिससे बंगाल में लोग भूखों मरने लगे

मधुश्री मुखर्जी अपनी किताब 'चर्चिल्स सीक्रेट वॉर' के मुताबिक, 27 जुलाई 1943 को आचीबॉल्ड वेवेल ने अपनी डायरी में लिखा था कि-

'बंगाल के अकाल को ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल बड़ा मुद्दा नहीं मानते बल्कि इसे लोकल इश्यू मानते हैं।'

4 अगस्त को ब्रिटिश पीएम चर्चिल के नेतृत्व में वॉर कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में बंगाल में भूख से मर रहे लोगों के लिए अनाज भेजे जाने का मुद्दा उठा। अधिकारियों ने तत्काल 5 लाख टन गेहूं भारत भेजने की सिफारिश की।

बैठक में चर्चिल ने यह कहते हुए भारत में अनाज भेजने से मना कर दिया था कि-

'खरगोश की तरह बच्चा पैदा करने वाले भारतीय लोग इस अकाल के लिए खुद जिम्मेदार हैं।'

वहीं, इसी बैठक में चर्चिल ने यूरोप के बाकी हि-स्सों में अनाज भेजने के आदेश दिए थे। ताकि जंग के दौरान अंग्रेज सैनिकों के लिए खाने की कमी न हो। भारत के फील्ड मार्शल रहे आचीबॉल्ड वेवेल ने बाद में अपनी डायरी में लिखा था कि बंगाल का अकाल औपनिवेशिक काल के दौरान सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक था। इससे ब्रिटिश सरकार की इमेज को जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकी।

अमेरिका और कनाडा ने मदद करनी चाही तो उसे भी चर्चिल ने ठुकराया

नेशनल मेडिसिन लाइब्रेरी वेबसाइट ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि अगस्त 1943 में कलकत्ता के मेयर सैयद बदरुद्दुजा ने अमेरिका राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को पत्र लिखकर जल्द से जल्द अनाज भेजने की अपील की थी।

ऐसा माना जाता है कि भारत को इमरजेंसी फूड सप्लाई करने के अमेरिकी सरकार के फैसले को विंस्ट-न चर्चिल ने ठुकरा दिया था। इतना ही नहीं, कनाडा ने जब 1 लाख टन गेहूं मदद के तौर पर भारत भेजना चाहा तो इस पर भी ब्रिटेन की एक कमेटी ने रोक लगा दी।

ब्रिटिश सरकार से मदद नहीं मिलने पर जब भार-तीय विधानसभा के लोगों ने संयुक्त राष्ट्र राहत और पुनर्वास विभाग से खाद्य सहायता मांगने की कोशिश की तो चर्चिल सरकार ने उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दी थी।

ये तस्वीर 1943 की है, जिसमें अकाल के दौरान बच्चे अंग्रेजों के लिए अनाज ले जा रही ट्रेन में लदी बोरियों में तारों के जरिए छेद करके अनाज जमा करने की कोशिश करते दिख रहे हैं।

दोस्त के बहकावे में आकर चर्चिल ने भारतीय लोगों को भूख से मरने दिया

विंस्टन चर्चिल ज्यादातर फैसले अपने दोस्त फ्र-ेडरिक लिंडमैन से सलाह करने के बाद लेते थे। फ्र-ेडरिक पीएम चर्चिल के इतने ज्यादा करीब थे कि उन्ह-ोंने उसे वॉर कैबिनेट का हिस्सा बनाया था।

इतना ही नहीं, फ्रेडरिक ने अलग-अलग मुद्दों पर सलाह देते हुए 2000 से ज्यादा मेमो चर्चिल को लिखे थे। इनमें से एक भारत में भूख से मर रहे लोगों के लिए अनाज नहीं भेजने को लेकर भी था।

चर्चिल ने भारत के सरकारी गोदामों में जमा अतिरि-क्त अनाज को भी श्रीलंका में तैनात अंग्रेज सैनिकों के लिए भेजने का आदेश दिया था। जब ऑस्ट्रेलिया से चलकर गेहूं से भरे जहाज भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचे तो अंग्रेज अधिकारियों ने इस जहाज को यहां से सीधे मध्य-पूर्व की तरफ भेज दिया।

अकाल को छिपाने के लिए अंग्रेजों ने सेंसरशिप का सहारा लिया

1943 में ब्रिटिश पीएम चर्चिल के बयानों और नीतियों से ऐसा लग रहा था कि उन्हें बंगाल में भूख से मर रहे लोगों की चिंता नहीं थी। वह दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान सिर्फ और सिर्फ भारतीय रिसोर्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने बंगाल में मर रहे लाखों लोगों की खबर को दबाने के लिए सेंसरशिप और प्रोपेगैंडा का सहारा लिया।

पीएम चर्चिल नहीं चाहते थे कि भारत में भूख से मर रहे लोगों की खबर उनके देश के लोगों तक पहुंचे। इसी वजह से उनकी सरकार ने इस अकाल के लिए जिम्मेदार भारत की जमींदारी प्रथा और मानसून को बताना शुरू कर दिया।

मार्च 1943 से अक्टूबर 1943 तक किसी को भी अकाल पर रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं थी, लेकि-न स्टेट्समैन अखबार के संपादक इयान स्टीफेंस ने कलकत्ता की गलियों और सड़कों पर पड़ी लाशों की तस्वीरें छापकर अकाल की डरावनी तस्वीरों को दिखाने की कोशिश की। इसके करीब छह महीने बाद ब्रिटिश संसद ने ये स्वीकार किया कि बंगाल विनाशकारी अक-ाल की चपेट में है।

चांद का मालिक कौन, यहां कौन बेचता है जमीन, आखिर कैसे होती है रजिस्ट्री?

चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लांच हो गया है और अब इसके 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर पहुंचने की उम्मीद है. इस बीच ये सवाल फिर से लोगों के मन में आ रहा है कि क्या वाकई में चंद्रमा पर जमीन खरीदी जा सकती है? चंद्रमा का मालिक कौन है? इसकी रजिस्ट्री कहां और कैसे होती है? जमीन कितने में मिल रही है और किन किन बड़े सेलिब्रिटीज ने जमीन खरीदी है?

दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने चांद पर जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था, जबकि शाहरूख खान को ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले उनके एक फैन ने चांद पर जमीन खरीदकर गिफ्ट की थी. **Lunaregistry.com** के मुताबिक, चांद पर एक एकड़ जमीन की कमत वरऊ 37.50 यानि करीब 3075 रूपए है.लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर चांद का मालिक है कौन?

Outer Space Treaty 1967 के मुताबिक, अंतरिक्ष में या फिर चांद या फिर बाकी ग्रहों पर किसी भी एक देश या व्यक्ति का अधिकार नहीं है. **Outer Space Treaty** के मुताबिक, चांद पर बेशक किसी भी देश का झंडा लगा हो, लेकिन चांद का मालिक कोई नहीं बन सकता.

Outer Space Treaty कुछ ऐसे कामों और नियमों की लिस्ट है, जिसे लिखित में हस्ताक्षर करके साल 2019 तक कुल 109 देश जुड़ चुके हैं. 23 अन्य देशों इन भी इस पर साइन कर दिए हैं, लेकिन अभी इनको मान्यता मिलना बाकी है. इस **Treaty** में लिखा है कि चांद पर कोई भी देश विज्ञान से जुड़ा अपना रिसर्च काम कर सकता है और उसका इस्तेमाल इंसान के विकास में कर सकता है, लेकिन उस पर कब्जा नहीं कर सकता. सवाल ये कि जब चांद पर किसी देश का मालिकाना हक है ही नहीं तो फिर कंपनियां कैसे चांद पर जमीन बेच रही हैं?

Outer Space Treaty 1967 के मुताबिक, अंतरिक्ष में या फिर चांद या फिर बाकी ग्रहों पर किसी भी एक देश या व्यक्ति का अधिकार नहीं है. **Outer Space Treaty** के मुताबिक, चांद पर बेशक किसी भी देश का झंडा लगा हो, लेकिन चांद का मालिक कोई नहीं बन सकता.

Outer Space Treaty कुछ ऐसे कामों और नियमों की लिस्ट है, जिसे लिखित में हस्ताक्षर करके साल 2019 तक कुल 109 देश जुड़ चुके हैं. 23 अन्य देशों इन भी इस पर साइन कर दिए हैं, लेकिन अभी इनको मान्यता मिलना बाकी है. इस **Treaty** में लिखा है कि चांद पर कोई भी देश विज्ञान से जुड़ा अपना रिसर्च काम कर सकता है और उसका इस्तेमाल इंसान के विकास में कर सकता है, लेकिन उस पर कब्जा नहीं कर सकता. सवाल ये कि जब चांद पर किसी देश का मालिकाना हक है ही नहीं तो फिर कंपनियां कैसे चांद पर

सीमा हैदर की तरह प्यार के लिए अड़ी सोनिया अख्तर : बांग्लादेशी महिला बोली- चाहे 10 करोड़ रुपए दें, फिर भी ग्रेटर नोएडा से लेकर जाऊंगी

गौतमबुद्ध नगर में पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के बाद बांग्लादेशी महिला सोनिया अख्तर आ गई है। एक वीडियो सोनिया अख्तर का सोशल मीडिया के जरिए सामने आया है। जिसमें वह बोल रही है कि चाहे उनको 10 करोड़ रुपए का ऑफर दें, लेकिन स्वीकार नहीं करेंगी। वह केवल अपने पति को लेकर जाएगी। यह उनकी और उनके बेटे की जिंदगी का सवाल है।

''उसने मुस्लिम धर्म अपनाया था''

सोनिया अख्तर का कहना है, ''इस मामले में जांच चल रही है और बहुत जल्द सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। डीसीपी मैडम ने सौरभ कांत तिवारी को बुलाया और पूछताछ की। जिसमें सौरभ कांत ने बताया कि उसने मुस्लिम धर्म अपनाया था और मुझसे शादी की थी। हमारा एक बच्चा भी है।''

उसको मेरा साथ निभाना ही पड़ेगा

सोनिया ने आगे कहा, ''जब इतनी सब बात है तो मुझे लेकर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा हैं। मुझे एक करोड़ की जगह 10 करोड़ रुपए पर देंगे, तब भी मैं सौरभ कांत तिवारी को तलाक नहीं दूंगी और ना ही मैं उसको छोड़ने वाली हूं। मैं उसके साथ रहूंगी। मैंने उसके साथ शादी किया है। उसको मेरा साथ निभाना ही पड़ेगा।''

छोटा-मोटा हंगामा करके वापस लौट गई थी सोनिया अख्तर

सूरजपुर थाना क्षेत्र में स्थित शिवालिक होम्स हाउसिंग सोसायटी में सौरभ कांत तिवारी अपने परिवार के साथ रहता है। सौरभ कांत तिवारी की बीवी सरकारी टीचर है और उनके 20 साल का बेटा है। सोसाइटी के लोगों ने बताया कि करीब 2 महीने पहले सोनिया अख्तर अपने बेटे को लेकर पहुंची थी। उन्होंने यहां पर अपने पति को वापस ले जाने के लिए छोटा-मोटा हंगामा भी किया, लेकिन

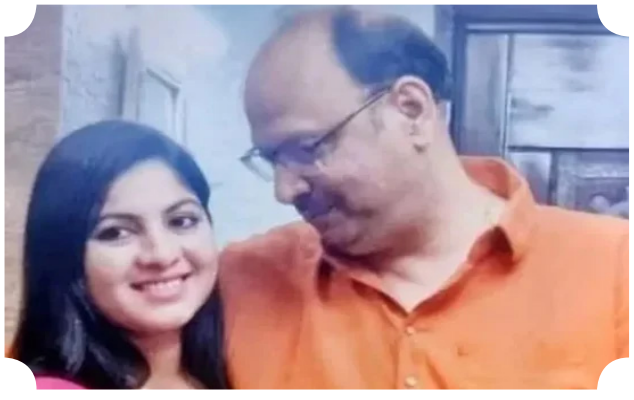

बाद में वह अचानक चली गई थी। सोसाइटी में चर्चा है कि कुछ आश्वासन मिलने के बाद सोनिया अख्तर वापस चली गई होगी, लेकिन जब उसका पति वापस नहीं लौटा तो दोबारा से वह अपने बच्चों को लेकर गौतमबुद्ध नगर पहुंची। अब दोबारा से सोनिया अख्तर अपने पति को लेने वापस आई है। सोनिया ने पुलिस से कहा है कि वह अपने पति को वापस लेकर जाएंगी।

पुलिस ने कहा- अभी मामला संज्ञान में आया

इस मामले में सूरजपुर थाना प्रभारी अवधेश प्रताप सिंह का कहना है कि सोनिया अख्तर का मामला अभी उनके संज्ञान में आया है। वह 2 महीने पहले आई थी, इसके बारे में उनका कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल इस मामले में नोएडा पुलिस की महिला स्पेशल टीम जांच कर रही है। जांच के आधार पर आगे एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल बांग्लादेशी महिला सोनिया अख्तर नोएडा पुलिस की निगरानी में है।

दोनों की उम्र में 15 वर्ष का फर्क

पूछताछ के दौरान सौरभकांत ने पुलिस को बताया कि उसने जानबूझकर मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया था, उसको जबरदस्ती मुस्लिम बनाया गया था। उसका धर्म परिवर्तन हुआ और उसने फिर सोनिया अख्तर से निकाह पढ़वाया गया था। दोनों का निकाह 14 अप्रैल 2021 को हुआ। निकाह बांग्लादेश से रीति-रिवाज के साथ हुआ था। सौरभकांत और सोनिया की उम्र में करीब 15 वर्ष का फर्क है।

दोनों एक कंपनी में करते थे काम

सोनिया अख्तर लगातार पुलिस से यही बात कह रही है कि सौरभकांत ने किसी जोर जबरदस्ती में निकाह नहीं किया था। उसने उसके साथ लव मैरिज की थी। सौरभकांत तिवारी एक आईटी कंपनी में काम करता है। वह कंपनी की तरफ से बांग्लादेश नौकरी के लिए गया था। इस दौरान दोनों की मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि जिस कंपनी में सौरभकांत तिवारी काम करता था, उसी कंपनी में सोनिया अख्तर भी काम करती थी।

सौरभकांत का बड़ा बेटा 20 और छोटा बेटा एक साल का

सोनिया अख्तर का आरोप है कि सौरभकांत ने अपनी पहली शादी को छुपाते हुए उससे निकाह किया। इसकी फोटो उसके पास उपलब्ध है। सोनिया अख्तर ने अपनी शादी के सबूत नोएडा पुलिस को दिखाएं हैं। इसके बाद पुलिस ने सौरभकांत से पूछताछ की। अभी तक की जांच में पता चला है कि सौरभकांत की पहली बीवी के बेटे की उम्र 20 साल है और सौरभ कांत की दूसरी बीवी यानी कि सोनिया अख्तर के बेटे की उम्र केवल एक वर्ष है।

नेपाल में दिनेश गोप ऐसे करता था अपने सहयोगियों से संपर्क

स्थानीय लोगों के बीच बना ली थी अच्छी पकड़

एनआइए द्वारा गिरफ्तार पीएलएफआइ सुप्रीमो दिनेश गोप पिछले एक वर्ष से नेपाल में था. वहीं से वह झारखंड में संगठन चला रहा था. नेपाल में रहने के दौरान वहां के स्थानीय लोगों से दिनेश गोप ने संपर्क बढ़ाकर अपनी अच्छी पकड़ बना ली थी. इस कारण वह वहां आराम से रहता था. झारखंड में पीएलएफआइ के अन्य उग्रवादियों द्वारा वसूले गये लेवी के पैसे उसके कुछ समर्थक उस तक नेपाल पहुंचाने का काम करते थे..

इसमें सबसे प्रमुख सहयोगी के रूप में नीलांबर गोप का नाम सामने आ चुका है. नीलांबर गोप को खूंटी पुलिस एक अन्य समर्थक के साथ पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. दिनेश गोप कभी भी किसी से सामान्य कॉल पर बात नहीं करता था. वह इंटरनेट कॉल और विदेशी नंबरों से अपने सहयोगी से बात करता था. खबर यह भी है कि दिनेश गोप ने लेवी में वसूले पैसे को नेपाल में भी निवेश

किया है. हालांकि यह अभी जांच का विषय है..

खुफिया एजेंसी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिनेश गोप के नेपाल में होने की जानकारी झारखंड पुलिस के साथ-साथ एनआइ, स्पेशल ब्रांच और राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी को भी थी. कुछ माह पूर्व उसे नेपाल से झारखंड पुलिस की एक टीम ने पकड़ने का प्रयास किया था. लेकिन वहां की स्थानीय पुलिस ने झारखंड पुलिस को उतना सहयोग नहीं किया..

इसके बाद नेपाल में दिनेश गोप के होने की जानकारी वहां की खुफिया एजेंसी को दी गयी.

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड पुलिस के साथ एनकाउंटर के दौरान जब दिनेश गोप को गोली लगी थी, तब वह नेपाल भाग गया था. वहां वह किसी पीएलएफआइ उग्रवादी को मिलने के लिए नहीं बुलाता था. उग्रवादियों के बजाय वह अपने विश्वसनीय समर्थकों को बुलाता था''

मुगलों ने नेपाल पर कभी आक्रमण क्यों नहीं किया?

.सल्तनत की भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास पर गहरी छाप है। अपने करीब 300 वर्षों के शासन के दौरान मुगलों ने भारत और इसके आसपास के एक बड़े भू-भाग पर राज किया। उन्होंने अपनी सल्तनत को दक्षिण भारत में भी फैलाने की कोशिश और इसमें काफी हद सफल भी रहे।

लेकिन, तीन सदी तक शासन करने के बावजूद मुगलों ने कभी नेपाल पर अधिकार करने का प्रयास नहीं किया, जिससे उत्तर भारत की जमीनी सीमा लगती है। मुगलों ने मैदानी भाग पर कब्जे के लिए राजपूतों और दक्षिण में मराठाओं से लगातार संघर्ष किया। ऐसे में उनका कभी नेपाल का रुख नहीं करना हैरान करता है, क्योंकि नेपाल की सामरिक और व्यापारिक नजरिए से अपनी एक खास अहमियत थी।

मुगल वंश की नींव रखने वाले बाबर और उसके बेटे हुमायूं के बारे में माना जा सकता है कि उनका ज़्यादातर वक़्त आसपास के राजाओं से संघर्ष में बीता। इसलिए उन्हें नेपाल जैसे देश पर आक्रमण का समय नहीं मिला होगा। लेकिन, अकबर और औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सल्तनत काफी ताकतवर और स्थिर थी। वे नेपाल पर अधिकार जमा सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी कोशिश तक नहीं की।

मुगलों के नेपाल पर आक्रमण ना करने की वजह जानने से पहले उन दो मुस्लिम शासकों के बारे में जान लेते हैं, जिन्होंने नेपाल पर अधिकार करने का प्रयास किया था। नेपाल पर पहली बार हमला किया बंगाल के शम्सुद्दीन इलियास शाह ने, सन 1349 में। उसने नेपाल की राजधानी काठमांडू को लूटा, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे पीछे हटना पड़ गया। फिर 18वीं सदी में एक और बंगाली सुल्तान मीर कासिम ने नेपाल पर आक्रमण किया। लेकिन, मीर कासिम का हमला बुरी तरह नाकाम रहा। नेपाली गोरखाओं ने उसे आसानी से खदेड़ दिया।

- नेपाल पर हमला करने में सबसे बड़ी बाधा थी उसकी भौगोलिक स्थिति। दुनिया की शीर्ष 10 पर्वत चोटियों में से आठ नेपाल में ही हैं, जो उसे कुदरती कि ला बना देती हैं। मुगल सेना की जान हाथी, घोड़े और ऊंट थे। लेकिन, पहाड़ी रास्तों पर इन जानवरों को ले जाना, वो भी युद्ध के साजोसामान के साथ, काफी मुश्किल काम था।

- हिमालय की जमा देने वाली ठंड से निपटना भी एक बड़ी चुनौती थी। मुगल सैनिकों को इस तरह के मौसम से लड़ने का तजुर्बा नहीं था। बंगाल के सुल्तान शम्सुद्दीन ने जब नेपाल हमला किया था, तब उसकी सेना को भी घाटी की सर्दी ने काफी नुकसान पहुंचाया। उसके सैनिक मलेरिया और दूसरी बीमारियों के शिकार हो गए और उसे जल्द ही नेपाल छोड़कर वापस भागना पड़ा।

- नेपाल को जीतना आर्थिक तौर पर ज़्यादा फायदेमंद नहीं था। ऐसा नहीं है कि नेपाल कोई बेहद गरीब मुल्क था। काठमांडू की वास्तुकला और बुनियादी ढांचे से उसकी समृद्धि का पता चलता है। साथ ही, वह उस वक़्त प्रमुख व्यापारिक मार्ग भी था। लेकिन, इस आर्थिक संपन्नता के बावजूद नेपाल पर आक्रमण घाटे का सौदा था, क्योंकि जितना धन वहां से मिलता, उससे अधिक युद्ध की तैयारियों पर खर्च हो जाता।

- मुगलों को नेपाल की ओर से कोई खतरा भी नहीं था, जिससे वे उस पर आक्रमण करते। उलटे नेपाल ने तिब्बत में मुगल व्यापार के फलने-फूलने की राह खोली। उन पर हमला करने से तिब्बत के साथ मुगल व्यापार को जाहिर तौर पर नुकसान पहुंचता। किसी हमले का प्रभाव तिब्बत के साथ उनके व्यापार तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि लद्दाख और हिमालय क्षेत्र के अन्य राज्यों में मुगल अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता।

एक अंदाजे.के मुताबिक, अपने चरम पर मुगल फौज की कुल तादाद नौ लाख से भी अधिक थी। इसमें भारतीय, अरबी, अफगानी और ईरानी के साथ यूरोपीय लोग तक शामिल थे। ऐसे में उनके लिए सारी परेशानियों को दरकिनार करके नेपाल को जीतना बाएं हाथ का खेल होता। लेकिन, मुगल हर चीज को रणनीतिक नजरिए से देखते थे। जब तक कोई राज्य उनके लिए उपयोगी ना हो, वे उस पर अपना समय, शक्ति और दूसरे संसाधन बर्बाद नहीं करते।

अगर मुगल सारा जोखिम उठाकर नेपाल को जीत भी लेते, तो भी उनके लिए वहां अपनी सत्ता को कायम रख पाना काफी मुश्किल होता। नेपाल में हिंदू और बौद्ध धर्म को मानने वाले पहाड़ी लोग थे। वे मुस्लिम शासन के खिलाफ आखिर में विद्रोह कर देते। अकबर और औरंगजेब जैसे मुगल बादशाहों का अधिकतर वक़्त विद्रोह को दबाने में ही बीता। लेकिन, नेपाल का विद्रोह दबाना उनके लिए काफी मुश्किल होता, क्योंकि वहां दोबारा सैन्य सहायता भेजने के लिए भी पहले की तरह परेशानी उठानी पड़ती।

भारत और चीन जैसे ताकतवर देशों के बीच होने के बावजूद नेपाल ने अपनी मूल पहचान बनाकर रखी है। उस पर किसी आक्रमणकारी संस्कृति की छाप नहीं दिखती है, जो भारत जैसे देश में आसानी से नजर आ जाती है। ऐसे में अक्सर दावा किया जाता है कि गोरखा साम्राज्य और उसके सैनिक काफी बहादुर थे, जिनके खौफ की वजह से किसी ने उन पर आक्रमण नहीं किया। लेकिन, हकीकत में नेपाल ने ऐसी कोई जंग ही नहीं लड़ी, जिसने उनकी बहुप्रचारित बहादुरी का कड़ा इम्तिहान लिया हो। नेपाल का सबसे मजबूत पक्ष असल में उसकी भौगोलिक स्थिति ही थी। यहां तक कि अंग्रेजों ने भी पूरे नेपाल को जीतने की जहमत नहीं उठाई। 1814 में एंग्लो-नेपाली युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने नेपाल के सबसे लाभदायक हिस्से पर ही कब्जा किया। उनका भी यही मानना था कि पूरे नेपाल को जीतने में कोई फायदा नहीं। इसमें नफा कम होगा, नुकसान ज़्यादा।

यह समाचार पत्र मासिक महाराष्ट्र क्राईम्स मालिक, मुद्रक प्रकाशक सिराज चौधरी द्वारा राजीव प्रिंटर्स, ४९६, पंचशील नगर१, नागसेन बुद्ध मंदिर रोड नं३, तिलक नगर, चेम्बुर, मुंबई४०००८९ से मुद्रित करवा कर ८/ऐ/१६९/२७०२/टागोर नगर, विक्रोली (पू), मुंबई४०००८३ से प्रकाशित किया । RNI NO. : MAHHIN/1998/02261

संपादक सिराज चौधरी मो. ७७७७०६०६८७ www. maharashtracrimes. in / www. maharashtracrimes. blogspot. in Email : editor@maharashtracrimes. in / maharashtracrimes@gmail. com